



शिवशंकर आयुर्वेदिक

क्या डायबिटीज से परेशान हो ?
डायबेटीज चेकअप करके

पर Dr. B.A.M.S., M.D. अनुभवी चिकित्सक द्वारा चिकित्सा उपचार किया जाता है।

तथा दमा, अस्थमा, एलर्जी / सभी प्रकार के वात रोग / लखवा / स्त्रिरोज / पुरुष के शुक्राणू दोष / निसंतान / किडनी स्टोन / डायबिटीज से परेशान / वेट लॉस / वेट गेन / पिपल्स / फ्रेअरनेस / स्किन प्रॉब्लेम / पाईल्स / एवं अन्य बिमारीयों पर भी उपचार किया जाता है।

नागपुर का भव्य शोरूम महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार, सिताबर्डी, नागपुर.
फोन : 9112079000 / 8605245080
आयुर्वेदिक दवाईया तथा जड़ीबुटीयों का विशाल भंडार

खबरें! एक नजर में!!**प्रयागराज महाकुंभ**

के लिए खुला खजाना
प्रयागराज। 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन योगी और मोदी सरकार ने महाकुंभ के लिए खजाना खोल दिया है। जनवरी महीने में शुरू हो रहे इस आयोजन से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। इसकी पहली किस्त 1050 करोड़ रुपये जारी भी हो गई है।

राहुल गांधी**आज संभल दौरे पर**

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ आज बुधवार को संभल का दौरा करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा भी राहुल के साथ संभल का दौरा कर सकती हैं। उन्होंने कहा, 'प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी 6 सांसद शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे।

दाचीगाम जंगल**में एक आतंकी ढेर**

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के दाचीगाम वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस समय सुरक्षाबलों ने आतंकीयों की गोलीबारी का जवाब दिया। जानकारी के अनुसार, विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और गलाशो अभियान शुरू किया था। जिसमें ये आतंकी मारा गया।

आज इसरो लॉन्च**करेगा प्रोबा-3 मिशन**

नई दिल्ली। भारत स्पेस साइंस के क्षेत्र में लगातार नाम बना रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अब तक कई कीर्तमान रचे हैं। अब इसरो के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। इसरो आज बुधवार को प्रोबा-3 मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने कहा पीएसएलवी-सी 59 रॉकेट/आरओबीए-3 मिशन के लिए हमसे लाइव जुड़े। इस मिशन में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड सहयोग कर रही है।

किश्तवाड़ में जवान**की गोली लगने से मौत**

किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गोली लगने के चलते एक 24 साल के जवान की मौत हो गई। सर्विस गन से गलती से गोली चल गई, जो एक सिपाही को जा लगी। मृत सिपाही की पहचान सतनाम सिंह के रूप में हुई है, जो जम्मू का रहने वाला था। हादसा किश्तवाड़ जिले के चिचू इलाके में हुआ। गन से गोली कैसे चल गई इस पर अभी जांच जारी है।

सड़क हादसे में 5**एमबीबीएस छात्रों की मौत**

चेन्नई। केरल के अलपुझा में सोमवार देर रात केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस का कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार पांच एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना कलारकोड के पास हुई। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि टक्कर के कारण कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वाहन को तोड़कर उसमें बैठे लोगों को बाहर निकाला गया।

आतंकीयों के मददगार**दो महिलाएं गिरफ्तार**

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप है। एसएसपी आमोद अशोक नागपुर ने जानकारी दी कि यह गिरफ्तारी 11 सितंबर को कांउंटर टेरर ऑपरेशन के बाद की गई, जिसमें दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे।

पाँश एक्ट का पालन नहीं होना चिंताजनक

नई दिल्ली।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का राष्ट्रीय अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया। मामले में न्यायमूर्ति बी वी नागरला और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि पाँश अधिनियम को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर, 2024 तक प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो 31 जनवरी, 2025 तक एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा और तालुका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। शीर्ष अदालत ने उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को पाँश अधिनियम की धारा 26 के तहत आंतरिक शिकायत समिति अनुपालन के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सीबीएसई 10वीं और 12वीं**प्राैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से**

नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से दोनों ही कक्षाओं के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। जारी की गई अधिसूचना के शिर्षक 'रेगुलर सेशन स्कूलों के छात्रों के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच करवाया जायेगा। छात्र ध्यान रखें कि वे प्रैक्टिकल परीक्षा में अवश्य शामिल हों नहीं तो रिजल्ट में आपको प्रायोगिक परीक्षा में अर्बसेंट प्रदर्शित किया जायेगा। सीबीएसई की ओर से सेकेंडरी एवं सीनियर

सेकेंडरी कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 15 फरवरी से की जाएगी। 10वीं कक्षा का पहला पेपर अंग्रेजी विषय का वहीं 12वीं कक्षा का एंटरप्रेनोरशिप विषय का आयोजित किया जाएगा। 10वीं कक्षा का अंतिम पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषयों के होंगे जिसका आयोजन 18 मार्च 2025 को किया जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट का अंतिम पेपर साइकोलॉजी विषय का होगा जिसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को करवाया जायेगा। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जाएगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे संपन्न करवाए जाएंगे। सीबीएसई की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र आपके संबंधित स्कूल में परीक्षा से कुछ दिन पूर्व भेज दिए जाएंगे।

कर्ज में दब रहे किसान**5 वर्ष पहले 14 लाख करोड़ ऋण****था, अब 25 लाख करोड़ के पार**

नई दिल्ली। देश में किसानों द्वारा लिया जाने वाला कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पांच साल पहले किसानों को दिए गए फसल ऋण की बात करें तो वह

महायुति में सीएम को लेकर बनी सहमति!

मुंबई।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नौ दिन से जारी सस्पेंस मंगलवार को समाप्त हो गया है। सूत्रों ने बताया कि 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे जबकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं, गृहमंत्रालय फडणवीस के पास ही रहेगा। सूत्रों के अनुसार, निर्वतमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा आलाकमान की बात मानकर सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तो तैयार हो गए थे, लेकिन नाराजगी के कारण

**फडणवीस-शिंदे में हुई आधे घंटे बातचीत**

11 महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की। फडणवीस सीएम हाउस वर्षा पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच अकेले में करीब आधे घंटे बातचीत हुई। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह दोनों की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों दिल्ली में मिले थे।

मंत्री बनने के मना कर रहे थे। बीते दिन शिंदे से बीजेपी नेता ने मुलाकात की थी। जिसके बाद शिंदे को मना लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, शिंदे को शहरी आखिरकार बीजेपी नेता गिरीश महाजन

की मध्यस्थता के बाद वह डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गए हैं। विकास और लोक निर्माण विभाग जैसे

सुको का निर्देश- सेवसुअल हैरिसमेंट पर राज्य कंफ्लेंट कमेटी बनाएं

नई दिल्ली।

गोवा विवि के पूर्व विभागाध्यक्ष की दायर याचिका पर निर्देश
शीर्ष अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय के बावजूद 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के प्रवर्तन में 'गंभीर चूक' को देखना 'चिंताजनक' है। इसे 'युद्ध स्थिति' बताते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सभी राज्य पदाधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी उपक्रमों पर खराब प्रभाव डालता है। अदालत का यह निर्देश गोवा विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष अरिंदित्याको फर्नंडीस की तरफ से दायर याचिका पर आया, जिन्होंने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

उन्होंने कहा कि वे आंतरिक शिकायत समिति के गठन और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ जुड़ेंगे। पीठ ने अपने निर्देशों के अनुपालन के लिए 31 मार्च, 2025 तक का समय दिया और मुख्य सचिवों को क्रियान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया। यह निर्देश न्यायालय के मई 2023 के

सेना को मिलेंगे ये खतरनाक वीपन्स**सरकार ने 22 हजार करोड़ के हथियार खरीद को दी मंजूरी**

नई दिल्ली।

रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश सुरक्षा हित में सरकार ने तकरीबन 22 हजार करोड़ रुपये के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भारत अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। इन हथियारों के मिलने के बाद चीन और पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएफपी ने 21,772 करोड़ रुपये के 5 रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इन प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वीकृत किया गया। दरअसल, इस डील के तहत मोदी सरकार का मकसद हर मोर्चे पर अपनी सैन्य

**सेना को मिलेंगे ये हथियार**

अधिग्रहण प्रस्ताव के तहत तटीय क्षेत्रों में निगरानी के लिए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (ईडब्ल्यूएस), नेक्स्ट जनरेशन के लिए रडार वर्किंग रिसीवर, एडवांस्ड लाइट हेल्थीकोप्टरों की खरीद को मंजूरी दी गई है।

ताकत को बढ़ाना है। खरीद के तहत वायुसेना, कोस्ट गार्ड्स, और थल सेना के लिए हथियार खरीदे जाएंगे। जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा करेगा। सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट के लिए इसकी खरीद को मंजूरी दी गई है। यह प्रणाली विमान को दुश्मन के रडार और हथियार प्रणालियों से

बचाने के साथ-साथ उनकी संचालन क्षमता को बढ़ाएगी। भारतीय नौसेना के लिए 31 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की खरीद की मंजूरी दी गई है। ये जहाज गश्त, बचाव और समुद्री डाकूओं के खिलाफ अभियानों के लिए डिजाइन किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स खरीद को भी मंजूरी दी है।

छोटे किसानों के लिए एक उप सीमा तय

11 वर्ष 2016 से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक उप सीमा तय की गई है, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है। यानी कुल कृषि ऋण का 56 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को जाना चाहिए। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और बैंकों के सहयोग से केसीसी के प्रचार और संतुष्टि के लिए नियमित रूप से अभियान और शिबिर आयोजित करता है।

कुल ऋण का 18 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र को प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के मुताबिक, सरकार पूरे भारत में केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित संशोधित ब्याज सबवर्षण योजना (एमआईएसएस) नामक केंद्रीय क्रेडिट योजना को कार्यान्वित कर रही है। इसका मकसद, किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। पिछले पांच वर्ष के दौरान किसानों को दिया गया कुल कृषि ऋण 25.47 लाख करोड़ रुपये है। साल 2019-20 में फसल ऋण 8.25 लाख करोड़ रुपये था। सावधि ऋण 5.68 लाख करोड़ रुपये था। कुल ऋण 13.93 लाख करोड़ रुपये था। साल 2020-21 में फसल ऋण 8.94 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस अवधि में सावधि ऋण 6.82 लाख करोड़ रुपये था। कुल ऋण 15.76 लाख करोड़ रुपये हो गया था। साल 2021-22 में फसल

- देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
- एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे
- गृह मंत्रालय फडणवीस के पास ही रहेगा

कल आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह

11 कल 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह को लेकर तैयारी जोरशोर से चल रही है। मुंबई के आजाद मैदान में इसका आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम भाजपा के दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई थी। महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 235 पर अपना कब्जा जमाया। वहीं, बीजेपी ने अकेले 132 सीटों पर जीत दर्ज की। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।

बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं। लेकिन इसके बदले शिंदे ने कई अहम पदों की मांग की है। शिंदे के अलावा पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी दो डिप्टी सीएम होंगे। एनसीपी

नेता अजित पवार को भी डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है। गिरीश महाजन की मुलाकात और शिंदे गुट के सांसदों के आग्रह के बाद महायुति का संकट सुलझ पाया है।

सीईसी की नियुक्ति की सुनवाई से सीजेआई हटे

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी और इसके लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा।

नीए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी

विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।

2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे, तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने

संभल हिंसा का**पाकिस्तानी कनेक्शन****बवाल में विदेशी कारतूस का हुआ इस्तेमाल**

संभल। इसी दौरान एक खोखा और एक कारतूस पुलिस को मिला है। इसके पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का होने का प्रमाण मिला है। इसी तरह यूएसए में बना एक 12 बोर का खोखा भी मिला है। 32 बोर के तीन खोखे मिले हैं। एसपी ने कहा कि अब जांच यह भी की जाएगी कि पाकिस्तान और यूएसए का कारतूस संभल तक कैसे पहुंचा और किस हथियार में इस्तेमाल किया गया। दस दिसंबर तक जिले में बाहरी रोक में इस्तेमाल किया गया। दस दिसंबर तक जिले में बाहरी रोक के बावजूद मंगलवार को जमीयत उलमा-ए-हिंद और कांग्रेसी नेता पीड़ित परिवारों से मिलकर चले गए। पुलिस-प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाहरी लोगों को रोकने में खुफिया तंत्र भी असफल रहा। जबकि अधिकारी लगातार निगरानी की बात कह रहे हैं। जमीयत उलमा ए हिंद के पदाधिकारियों ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।



सिगरेट और तंबाकू के बढ़ सकते हैं दाम

जीएसटी की मीटिंग में लिया जा सकता है फैसला

नई दिल्ली. जीएसटी के मीटिंग के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. यह बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होनी है. इस बैठक में कई बड़े फैसले और अहम बदलाव हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से छूट को लेकर फैसला लिया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी की यह बैठक होनी है. इस बैठक में कुछ अहम फैसलों में एक सिगरेट और तंबाकू पर



जीएसटी बढ़ाया जा सकता है. यह पहली बार नहीं है जब सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी बढ़ाया जा रहा हो. इससे पहले भी सरकार की तरफ से सिगरेट और तंबाकू पर टैक्स लगाया

गया है. जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के ग्रुप ने तंबाकू और सिगरेट से संबंधित प्रोडक्ट पर टैक्स को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है.

महंगे रेडीमेड कपड़ों पर लगेगा 28 फीसदी

शादीयों के सीजन में केंद्र सरकार की ओर से झटका मिल सकता है, दरअसल 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और इसमें ब्रांडेड कपड़े पर लगने वाले जीएसटी को बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपकी शादी दिसंबर महीने के बाद है और आपने अभी शादी के लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं तो इनके महंगे होने से पहले आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए. फिलहाल रेडीमेड कपड़ों पर चार स्लैब में अलग-अलग जीएसटी वसूला जाता है, जिसमें 5 से 28 फीसदी तक टैक्स है. वहीं 21 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद मंत्री समूह ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकता है.

नई 35 फीसदी दर भी शामिल होगी

यह डिजीनल रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा हो सकता है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सहाय चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रियों के ग्रुप ने सोमवार को इस दर को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की. तंबाकू पर 35 फीसदी की विशेष दर प्रस्तावित करने पर सहमत व्यक्त की है. इसके लिए 5 फीसदी, 12 फीसदी, और 28 फीसदी की मौजूदा चार स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर बनी रहेगी. इसमें नई 35 फीसदी दर भी शामिल होगी.

अडानी समूह ने किया शेयरधारकों को मालामाल?



जबकि साल 2024 में नवंबर महीने तक कंपनी ने 293.7 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया जो साल दर साल 7 फीसदी ज्यादा है. नवंबर महीने में कंपनी का लॉजिस्टिक रेल वॉल्यूम में साल दर साल 10 फीसदी का उछाल आया है. कंपनी के इसी फाइलिंग के चलते आज के सत्र में अडानी पोर्ट्स के शेयर में बंपर उछाल देखने को मिला है. 3 दिसंबर के कारोबारी सत्र में अडानी पोर्ट्स का स्टॉक 1225 रुपये पर खुला और 7.81 फीसदी के उछाल के साथ 1310 रुपये पर जा पहुंचा है. एक ही सत्र में स्टॉक में पिछले क्लोजिंग प्राइस लेवल 1215 रुपये से 95 रुपये का उछाल देखने को मिला है. स्टॉक में आई इस शानदार तेजी के बाद अडानी पोर्ट्स का मार्केट कैप 2.83 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है. एक ही दिन में कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 20000 करोड़ रुपये का इजाफा देखने को मिला है.

रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर

4 पैसे टूटकर 84.76 के स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली. विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निरंतर निकासी से निवेशकों की धारणा हुई मॉलवारा को सुरक्षाती कारोबार में रुपया 4 पैसे गिरकर 84.76 रुपये प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर पर आ गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि रुपए में गिरावट मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स मुद्रा पर बयानबाजी, यूरोजोन में राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर चेरलू आर्थिक संकेतक और विदेशी पोर्टफोलियो में निरंतर निकासी के कारण हुई। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को धमकी दी कि यदि BRIC समूह के देश अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा, बाजार सहभागियों 6 दिसंबर को आने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति से भी संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें

रिलायंस-ओएनजीसी को बड़ी सौगात



नई दिल्ली.

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और कूड ऑयल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है. शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के पटल पर वित्त मंत्रालय की ओर से इस फैसले की जानकारी देते हुए नोटिफिकेशन पेश किया गया है. साल 2022 में कच्चे तेल के दामों में तेज उछाल के बाद घरेलू कच्चे तेल, पेट्रोल डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट से तेल कंपनियों को होने वाले मुनाफे पर सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था. वित्त मंत्रालय ने विंडफॉल टैक्स खत्म करने के फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, कूड ऑयल के प्रोडक्शन, एटीएफ के एक्सपोर्ट और पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर लगाने वाले स्पेशल एडिशनल एक्ससाइज ड्यूटी और रोड-इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को वापस लेने का फैसला किया जाता है. कच्चे तेल के दामों में तेज गिरावट के बाद सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसले के

क्यास लंबे समय से लगाये जा रहे थे. वित्त मंत्रालय ने इस फैसले को फौन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. सरकार ने देश की ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल डीजल और एटीएफ के निर्यात से हो रहे बड़े फायदे के मद्देनजर विंडफॉल टैक्स लगाने का ऐलान किया था. सरकार ने पेट्रोल डीजल और एटीएफ के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया तो चेरलू कूड प्रोडक्शन पर भी सेस लगा दिया गया. साल 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते देश की सरकारी और खासतौर से प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी कंपनियों रूस से सस्ते में कच्चा तेल आयात कर उसे रिफाइन करने के बाद ऊंचे दाम पर विदेशों में पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन बेच रही थीं जिसे उन्हे जबरदस्त मुनाफा हो रहा है. जबकि घरेलू कच्चे तेल के भी एक्सपोर्ट पर भी ऑयल कंपनियों को फायदा हो रहा था जिसके चलते सरकार ने इन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था. ह 15 दिनों में सरकार विंडफॉल टैक्स का समीक्षा किया करती थी.

सोने-चांदी में दिखी गिरावट

नई दिल्ली.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख के बीच सोमवार को यानी आज देश की राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये की गिरावट के साथ 79,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. जबकि, शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली सोने की कीमत 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों और सिक्का बनाने वाले इकाइयों की कमजोर उठान के कारण चांदी भी 2,200 रुपये लुढ़ककर 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में



यह 92,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 200 रुपये गिरकर 78,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. जबकि, शुक्रवार

को सोना 79,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था. इंटरनेशनल लेवल पर कामिक्स (जिस बाजार) सोना वायदा 23.50 डॉलर प्रति औंस यानी 0.88 प्रतिशत गिरकर

2,657.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकरर्स के सहायक उपाध्यक्ष (जिस और मुद्रा) मनीष शर्मा कहते हैं, 'एशियाई कारोबार के दौरान 2,621 अमेरिकी डॉलर के दिन के कारोबार के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, सोने में गिरावट जारी रही.' शर्मा का कहना है कि यह गिरावट डॉलर में आये सुधार के कारण हुई. इसे अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित शुल्क दर से जुड़ी मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से बल मिला है.

सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली.

सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंडों से कहा कि वे खातों से किसी भी प्रकार की डेबिट की अनुमति न दें। पिछले सप्ताह नियामक ने कंपनी से घन के अवैध हस्तांतरण के लिए 78 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए तीन संस्थाओं को कुर्की नोटिस भेजा था। आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हार्ड-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड। इस वर्ष अगस्त में सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के



पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से घन के हेर-फेर के लिए प्रतिभूति बाजार से पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें पांच साल के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख संबंधीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में

प्रतिभूति बाजार से जुड़ने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ए 26 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए उसके बैंक, डोमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जन्त करने का आदेश दिया है। यह कदम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अवैध फंड डायवर्सन के संबंध में नवंबर में जारी नोटिस के बाद उठाया गया है। बाजार नियामक ने 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब आरबीईपी

एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को एक नोटिस भेजा था और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के मामले में घन के अवैध डायवर्सन से संबंधित आरोपों पर इकाई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था। नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल थी। नोटिस के अनुसार, सेबी ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि चूककर्ता बैंक खातों और डोमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटारा कर सकता है और 'इससे, देय राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी'।

निवेश शिक्षा पहल डायवर्सिफाई स्मार्टली को किया लॉन्च

नई दिल्ली.

जीवन में, हमें अक्सर दो चरम सीमाओं के बीच चुनना होता है। इसी तरह, निवेश के मामले में किसी को अक्सर उन परिसंपत्ति वर्गों के बीच चयन करने की दृष्टि का सामना करना पड़ता है, जिसमें जोखिम के साथ रिटर्न वाले उच्च जोखिम वाली इक्विटी, कम जोखिम वाले डेट और महंगाई के खिलाफ बचाव वाले विकल्प के तौर पर कमोडिटी (सोना, चांदी आदि) के खिलाफ हेज शामिल है। लेकिन क्या हो अगर आप प्रोथ और स्थिरता के बीच संतुलन बनाकर दोनों का लाभ उठाया जाए? इसके लिए हाइब्रिड फंड को चुनें, जो एक बहुमुखी निवेश विकल्प है और यह एक सिंगल फंड में जोखिम और रिटर्न दोनों को संतुलित करता है। हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड स्कीम



हैं, जो परिसंपत्ति आवंटन और प्रोथ के लिए इक्विटी (स्टॉक), डेट उपकरणों (बॉन्ड, डिबेंचर, जमा प्रमाणपत्र) और/या सोना, चांदी आदि जैसी जितनों में निवेश करती हैं। ये फंड विभिन्न जोखिम जरूरतों को पूरा करते हैं और नए निवेश करने वाले व अनुभवी निवेशकों दोनों के लिए उपयुक्त एक विविध और लचीला निवेश विकल्प मुहैया कराते हैं। संतुलित जोखिम-रिटर्न: इक्विटी, डेट और/या कमोडिटी को मिलाकर, ये फंड विविध इक्विटी फंडों की तुलना में कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न देते हैं।

चल रही ब्रिज सह वनधारा परियोजना

नई दिल्ली.

ओडिशा सरकार का ग्रामीण विकास विभाग राज्य में 'ब्रिज सह वनधारा' परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा राज्य सरकार का नया विकास मंत्र है। इसे साकार करने के लिए ग्रामीण विकास को निरंतर महत्व दिया जा रहा है और 'ब्रिज सह वनधारा' परियोजना उस दिशा में एक नई कोशिश है। इससे जल स्तर बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी भी मजबूत हो रही है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका में भी सुधार हो रहा है। ओडिशा सरकार के जसपंक अंधिकारी विनायक मिश्रा के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर बनाई जा रही 'पुल-सह-वनधारा' परियोजनाएं राज्य के समग्र विकास में लाभकारी हैं। इनमें जून 2024 से नवंबर 2024 तक विभाग की ओर से 18 'ब्रिज-सह-वनधारा' परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

मदर डेयरी बनी भारत ऑर्गेनिक्स की पार्टनर

मुंबई/नागपुर.

भारत की अग्रणी विविध फूड कंपनी भारत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व की सस्मिडरी मदर डेयरी में 'भारत ऑर्गेनिक्स' की ऑर्गेनिक स्टोपल रेंज को दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध कराने के लिए एक्सक्लूजिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के रूप में साईन किया है। इस पहल के तहत मदर डेयरी एनसीआर में अपने बृथ नेटवर्क के ज़रिए 'भारत ऑर्गेनिक्स' के पैकड एवं सर्टिफाईड प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इस साझेदारी के साथ एनसीआर के बाजार में 'भारत ऑर्गेनिक्स आटा' और 'भारत ऑर्गेनिक्स स्वीटनर (गुडु)' का लॉन्च किया गया है। 100 फीसदी सर्टिफाईड अनाज से बना 'भारत ऑर्गेनिक्स आटा' शुद्धता और ताज़गी के साथ बेहतरान प्राकृतिक स्वाद देता है। इसी तरह 'भारत ऑर्गेनिक्स स्वीटनर (गुडु)' आम चीनी का सेहतमंद और प्राकृतिक विकल्प है। ये प्रोडक्ट्स सेहतमंद और स्थायी आहार की बढ़ती



मांग को पूरा करने में मददगार होंगे। इस अवसर पर श्री मनीष बंदलिशा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मदर डेयरी ने कहा, 'इस साझेदारी के साथ मदर डेयरी स्वस्थ एवं स्थायी भारत के निर्माण के लिए प्रयासत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एनसीओएल की विशेषज्ञता, हमारे व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उपभोक्ताओं के भरोसे के साथ हम किसानों की बढ़ती मांग को पूरा करने में योगदान देंगे। यह लॉन्च उच्च गुणवत्ता के ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने तथा परिवारों को स्वस्थ जीवनशैली के साथ सशक्त बनाने की

हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।' मदर डेयरी ने कई चैनलों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्राण्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनसीओएल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। उपभोक्ताओं के कल्याण एवं गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारत ऑर्गेनिक्स रेंज सफल के 300 स्टोर्स, दिल्ली एनसीआर में तकरवीन 10,000 जनरल ट्रेड आउटलेट्स तथा आधुनिक ट्रेड एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। यह साझेदारी पोषक एवं स्थायी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए ऑर्गेनिक फूड को सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

क्यों बढ़ रही प्रीमियम घरों की बिक्री ?



नई दिल्ली.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट बाजार में जुलाई से सितंबर 2024 की तिमाही के दौरान शानदार तेजी देखने को मिली है. मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में मांग बढ़ने के चलते बड़े और महंगे अपार्टमेंट्स की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है. एक्सपर्ट की मानें तो मेट्रो कनेक्टिविटी में सुधार और

पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है. 2024 की दूसरी तिमाही में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले घरों की बिक्री 20 फीसदी तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की 11 फीसदी हिस्सेदारी से काफी अधिक है. इस तिमाही में 1,500 वर्ग फीट से बड़े घरों की मांग भी बढ़ी है. आंकड़ों के अनुसार, इस तरह की संपत्तियों की बिक्री 28 फीसदी तक पहुंच गई है, जो कि एक साल पहले की तुलना में शानदार वृद्धि को दिखाता है. यह दर्शाता है कि घर खरीदारों की प्राथमिकता अब बड़े और अधिक सुविधाजनक घरों की ओर बढ़ रही है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद, जब काम और निजी जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता महसूस की गई.

- १- श्रद्धा सबुरी लॉटरी, साई मंदिर
- २- जय भोले लॉटरी, झेरी लॉन
- ३- न्यू बॉम्बे लॉटरी, लक्ष्मी भवन चौक धरमपेट
- ४- साई लॉटरी, पंचशील चौक
- ५- अनिल बंसोड लॉटरी, झारसीरानी चौक बर्डी
- ६- नरेंद्र लॉटरी, शिवम्
- ७- अनिल बंसोड लॉटरी
- ७- प्रवीण लॉटरी महाराष्ट्र बैंक मुंजे चौक सीताबर्डी
- ८- मयूरी लॉटरी, आकाशवाणी चौक
- ९- माँ आंबे लॉटरी, आगराम देवी
- १०- नितिन लॉटरी, रामबाग कॉलोनी, मेडिकल चौक
- ११- दिलीप लॉटरी, नर्सिंग टॉकीज, महाल
- १२ श्री गणेश लॉटरी नर्सिंग टॉकीज, महाल
- १३- शुभम लॉटरी नर्सिंग टॉकीज, महाल
- १४ श्री गजानन लॉटरी जेन्डा चौक, महाल
- १५- आशीष लॉटरी शाहिद चौक, इतवारी
- १६- ख्वाजा लॉटरी कमाल टॉकीज, कमाल चौक
- १७- वैभव लॉटरी इंदौरा चौक लक्ष्मी बाग
- १८- चिकटे लॉटरी सक्करदारा चौक
- १९- ओमसाई लॉटरी,महाकालकर बिल्डिंग, छोटा ताजबाग
- २०- गुरुदेव लॉटरी, गांधीचौक
- २१- गजानन लॉटरी, अकोला
- २२- प्रेम लॉटरी सेंटर, कमाल चौक
- २३- नारायण लॉटरी, शहीद चौक, इतवारी
- २४- महावीर लॉटरी, बाजार चौक, कलमेश्वर

पहिले बिक्रि कर.	7 लाख	पहिले बिक्रि कर.	3784
5000/-	1000/-	500/-	200/-
1357	2809	1012	1338
3933	3050	1456	1338
5672	4382	3235	4152
5713	5949	5323	5030
6377	5895	5501	5850
6940	5966	6548	6211

सहारे बक्रीस रु.	300/- (सर्व मालिकोंसाठी)
1000	1000
1005	1005
1010	1010
1015	1015
1020	1020
1025	1025
1030	1030
1035	1035
1040	1040
1045	1045
1050	1050
1055	1055
1060	1060
1065	1065
1070	1070
1075	1075
1080	1080
1085	1085
1090	1090
1095	1095
1100	1100
1105	1105
1110	1110
1115	1115
1120	1120
1125	1125
1130	1130
1135	1135
1140	1140
1145	1145
1150	1150
1155	1155
1160	1160
1165	1165
1170	1170
1175	1175
1180	1180
1185	1185
1190	1190
1195	1195
1200	1200
1205	1205
1210	1210
1215	1215
1220	1220
1225	1225
1230	1230
1235	1235
1240	1240
1245	1245
1250	1250
1255	1255
1260	1260
1265	1265
1270	1270
1275	1275
1280	1280
1285	1285
1290	1290
1295	1295
1300	1300
1305	1305
1310	1310
1315	1315
1320	1320
1325	1325
1330	1330
1335	1335
1340	1340
1345	1345
1350	1350
1355	1355
1360	1360
1365	1365
1370	1370
1375	1375
1380	1380
1385	1385
1390	1390
1395	1395
1400	1400
1405	1405
1410	1410
1415	1415
1420	1420
1425	1425
1430	1430
1435	1435
1440	1440
1445	1445
1450	1450
1455	1455
1460	1460
1465	1465
1470	1470
1475	1475
1480	1480
1485	1485
1490	1490
1495	1495
1500	1500

पहिले बिक्रि कर.	7289	1554	0367	4173	3823
10,000/-	7289	1554	0367	4173	3823

सर्व मालिकोंसाठी	0268	9506
दुसरे बिक्रि कर.	0268	9506

पहिले बिक्रि कर.	1202	2634	3476	5397	8149
2000/-					

सुविचार

अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें. किस्मत की आजमाईश तो जुए में होती है..

संपादकीय

डॉलर की चिंता



अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपनी दूसरी पारी की औपचारिक शुरुआत करने से पहले ही डॉनल्ड ट्रंप धमकी भरी घोषणाओं से समसनी फेलो लगे हैं। उनकी ताजा घोषणा ब्रिक्स देशों के नाम जारी की गई इस धमकी के रूप में आई है कि अगर इन देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उसका कोई विकल्प लाने का प्रयास किया तो उन्हें अमेरिकी बाजार से हाथ धोना पड़ सकता है। ध्यान रहे, ब्रिक्स में रूस और चीन जैसे फिजिकल अमेरिका विरोधी माने जाने वाले देश ही नहीं भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ ही अब इजिप्ट, ईरान भी हैं।

अक्टूबर सम्मेलन : ट्रंप का यह बयान ब्रिक्स देशों के अक्टूबर में हुए शिखर सम्मेलन का जवाब माना जा रहा है, जिसमें नॉन-डॉलर ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई थी। हालांकि सम्मेलन के आखिर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया था कि सिस्टम सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेशन जैसी वित्तीय

संरचना का विकल्प खड़ा करने की दिशा में अब तक ठोस कुछ नहीं किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ब्रिक्स को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसकी छवि ऐसी बने कि वह वैश्विक संस्थाओं की जगह लेना चाहता है। इसके बावजूद अगर ट्रंप इतने आशंकित हैं कि ब्रिक्स देशों से डॉलर का विकल्प खड़ा न करने की गारंटी मांग रहे हैं तो वह अकारण नहीं है। सच यह है कि समय-समय पर कई देशों ने नॉन-डॉलर ट्रांजेक्शन की गुंजाइश तलाशने का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयास किया है। खासकर, अमेरिका ने जिस तरह से 2012 में ईरान और 2022 में रूस को स्विफ्ट से बाहर करके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन की इस व्यवस्था पर अपना दबदबा साबित किया, उसके बाद ऐसे प्रयासों की ज़रूरत ज्यादा महसूस की जाने लगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉनल्ड ट्रंप की यह धमकी सौदेबाजों के मकसद से दी गई है या वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति पर संभालने के बाद सचमुच इस पर अमल करने वाले हैं। एकपक्षीय तरीके से डॉलर को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई थी। हालांकि सम्मेलन के आखिर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया था कि सिस्टम सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेशन जैसी वित्तीय



डॉ.सलीम खान, मुंबई



□ दिल्ली में साढ़े दस साल और गुजरात में 12 साल तक सरकार चलाने के बावजूद, मोदी और शाह की जोड़ी यह नहीं समझ पाई कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लड़ने वाले और दूसरे डरने वाले। जो लड़ने वाले होते हैं, वे कभी नहीं डरते, और जो डरने वाले होते हैं, वे कभी नहीं लड़ते। अगर नदीम खान डरने वालों में से होते, तो कब का मैदान छोड़कर भाग गए होते। लेकिन जब इंसान जुल्म करता है, तो वह अंदर से डर के कारण खोखला होने लगता है, जैसे मौजूदा शासक। डरपोक लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और वे अपनी ही परछाई से डरने लगते हैं। वर्तमान सरकार के साथ भी यही हो रहा है, नहीं तो वह नदीम खान को परेशान करने की कोशिश नहीं करती। इस मामले में, पुलिस की साजिश को उजागर करने का पूरा इंतजाम कुदरत ने ऐसा किया कि वह पूरी तरह बेनकाब हो गई, और अब उसके पास अपनी गलती छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा। नदीम खान दिल्ली में रहते हैं।

यह तमाशा अगर उनके शहर में उनकी मौजूदगी के दौरान होता, तो पुलिस इस तरह से बेनकाब नहीं होती। इन लोगों ने नदीम खान को परेशान करने के लिए 29 नवंबर की रात 9 बजे का समय चुना, जब वे बंगलुरु में अपने भाई के पास थे। प्रशासन ने सोचा कि अगर नदीम खान पकड़ में आ जाते, तो उन्हें शनिवार और रविवार जेल की हवा खिलाई जा सकती थी। लेकिन जिसे अल्लाह बचाए, उसे कौन पकड़ सकता है? इसलिए, 20 पुलिसवालों का दल केवल चौकीदार

नदीम खान: अब कलम छोड़ दूँ या और साहस के साथ लिखूँ?



प्रसिद्ध कवि सरफ़ाज़ बज़मी की यह कविता नदीम खान के लिए प्रस्तुत है: वक्त की आँखों में सदियों की थकन तू ही बता, अब कलम फेंक दूँ या और जसागत से लिखूँ। माबदौलत का ये फ़रमान मिला है मुझको, जुलम को जुलम भी ज़ालिम की इजाज़त से लिखूँ।

को धमकाकर खाली हाथ लौट आया। अगले दिन, सुबह-सुबह वे फिर ऑफिस पहुंचे और वहां मौजूद स्टाफ से पूछाजत करने लगे। उन्हें याद नहीं रहा कि यह वकीलों का ऑफिस है, जहां बैठे लोग कानून अच्छी तरह जानते हैं। जब उनके सामने सवालों की बौछार हुई, तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था और वे शर्मिंदा होकर वहां से भाग गए। इस छोपेपारी से डरने के बजाय, एपीसीआर के वकील उल्टा थाने पहुंच गए और पुलिस से कागजात दिखाकर पर जोर देने लगे। पुलिस के पास कागजात होते, तो दिखा देते। लेकिन जब कुछ नहीं था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वहां झूठ और धांधली नहीं चलेगी। मजबूरी में 30 नवंबर की दोपहर 12:48 बजे एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पुलिस की यह कार्रवाई 16 घंटे पहले ही शुरू हो गई थी। नदीम खान के दिल्ली लौटने का इंतजाम किए बिना उसी दिन शाम 5 बजे बंगलुरु पहुंच जाना प्रशासन

की तीसरी गलती थी। दिल्ली से बंगलुरु की दूरी 1740 किलोमीटर है, और हवाई यात्रा में लगभग तीन घंटे लगते हैं। इसके अलावा, हवाई अड्डे तक पहुंचने और वहां से उनके भाई के घर तक का समय मिलाकर कम से कम 6 घंटे का समय लगना तय था। यह लेख सत्ता के दमनकारी प्रयासों और एक साहसी व्यक्ति के धैर्य और सत्य की विजय की कहानी को उजागर करता है। इसका मतलब यह है कि सुबह 11 बजे से पहले ही यात्रा शुरू हो चुकी थी, जबकि एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई थी। बिना पहचान पत्र और सादे कपड़ों में गए थे चार लोग इस भ्रम में थे कि उन्हें देखकर नदीम खान डर के मारे बिना किसी सवाल-जवाब के उनके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। उन्होंने यह तक नहीं सोचा कि जब एपीसीआर के दफ्तर का स्टाफ कागजात दिखाने की मांग कर सकता है, तो उनके मुखिया ऐसा क्यों नहीं करेंगे, जबकि उन्हें सोचने और अन्य कानूनी विशेषज्ञों से सलाह

लेने का भी अवसर मिल चुका था। बंगलुरु पहुंचने के बाद पुलिसवालों को समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति उनके दबाव में आने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने वहां पांच घंटे तक बैठकर परिवार को परेशान किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास न तो वारंट था और न ही कोई नोटिस। सच तो यह है कि उनके पास सिर्फ धमकी और जबरदस्ती साथ चलने की मांग के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन यह धमकियां 'किंग खान' को साथ लाने के लिए काफी नहीं थीं। आखिरकार, परेशान होकर इन लोगों ने दिल्ली से नोटिस मांगाया। वह पता चला कि एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 353(2) और 61 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन सभी धाराओं में अधिकतम सजा 7 साल से कम है, इसलिए गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है।

इस तरह, अपने ही जाल में फंसा प्रशासन नाकामी और शर्मिंदगी के साथ लौट आया। नदीम खान को, इंशाअल्लाह, गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल जाएगी। मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले इस योद्धा को डराने की कोशिश प्रशासन को महंगी पड़ी। इस घटना से सिविल सोसाइटी में उत्थल-पुथल मच गई। प्रशांत भूषण, डॉ. सुनीलम, डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी और योगेंद्र यादव जैसे कई लोग नदीम खान के समर्थन में आ गए और सरकारी ज्वाइंटों की निंदा करने लगे। नदीम खान, जो भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, देश में हेर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। इस घटना पर बीजेए (भारत जोड़ो अभियान) ने दिल्ली पुलिस की गैरकानूनी और धमकी भरी

कार्रवाई की कड़ी निंदा की। बीजेए के विशेष बयान में कहा गया कि "नदीम खान मानवाधिकारों के प्रमुख कार्यकर्ता और यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया के संस्थापकों में से एक हैं। वे आम नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 30 नवंबर को बंगलुरु में बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रयास न केवल गैरकानूनी बल्कि हास्यास्पद था। दिल्ली पुलिस द्वारा एक कुख्यात सांप्रदायिक ट्रोलेर के ड्रॉट के आधार पर नदीम खान पर नफरत फैलाने का आरोप लगाना आक्षेपजनक है। इस बयान में एपीसीआर (एफोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स) की एक प्रदर्शनी के दौरान किए गए न्यायिक कार्यों को घृणा अपराधों में गिनने को मूर्खता बताया गया है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का एक जानबूझकर और दुर्धनवादीपूर्ण प्रयास करार दिया गया। दिल्ली पुलिस की इस धमकाने वाली कार्रवाई की निंदा करते हुए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई।" मानवाधिकारों के संदर्भ में मानवाधिकारों की सबसे प्रमुख संस्था "द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज" ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की अवैध हरकत की कड़ी निंदा की है। संस्था ने पुलिस की जल्दबाजी और बिना किसी वारंट के या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नदीम खान और उनके परिवार को छह घंटे तक डराने-धमकाने और जबरदस्ती करने की आलोचना की। सोशल मीडिया पर दक्षिणपूर्वी समूह नदीम खान को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे पुलिस की ज्वाइंटियों और बीजेए हिंसा में राज्य की भागीदारी की कड़ी

आलोचना करते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। मॉब लिंगिंग और बीजेए हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नदीम खान और एपीसीआर के खिलाफ दुर्धनवादीपूर्ण प्रचार किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक प्रदर्शनी आयोजित करके घृणा अपराधों और बीजेए हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उजागर किया था। प्रसिद्ध वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विप्लव श्रीनिवास ने इस पुलिस ज्वाइंटरी पर कहा, "नदीम खान के मामले में दिल्ली पुलिस का रवैया पूरी तरह से अनुचित है। यह गंभीर संदेह पैदा करता है और कानून में जनता का विश्वास कमजोर करता है।" उन्होंने कहा कि नदीम खान और एपीसीआर को निःस्वार्थ रूप से पीड़ितों की आवाज बनने के कारण निशाना बनाया जा रहा है, और इस निंदनीय हरकत के खिलाफ कानूनी सरकार को कदम उठाना चाहिए। प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण ने नदीम खान के साथ अपनी तस्वीर "एक्स" (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए एक विस्तृत बयान लिखा। इसका सार यह है: "संप्रदायिक अपराधों को उजागर करने के लिए एपीसीआर के सचिव नदीम खान को दिल्ली पुलिस द्वारा परेशान करना यह दुर्लसा है कि पुलिस इन अपराधों में शामिल है। ऐसे पुलिस अधिकारियों को निर्लंबित किया जाना चाहिए और उन्हें अपराधिक धमकी देने के लिए मुकदमे का सामना करना चाहिए।" दुनिया भर के न्यायप्रिय लोग प्रशांत भूषण के विचारों का समर्थन करते हैं और नदीम खान के साथ खड़े हैं।

संस्मरण

मसखरा



○ जिस बस्ती में मेरा घर है वह पहले एक गांव था, नये राज्य बने, विकास हुआ, जो पहले जिला परिषद के क्षेत्र में आता था अब वह नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आ गया। नगर निगम के परिसीमन में नगर निगम ने हमारे गांव को भी शामिल कर लिया, उससे जहाँ कुछ फायदे हुए वहाँ कुछ हानि भी हुई, लेकिन हानि न के बराबर ही है। चूंकि पहले मेरा गांव शहर सीमा से सटा हुआ था।

अतः मूलभूत सुविधाएँ उसमें थी ही लेकिन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते ही वहाँ जो कर्मी रह गयी थी वह भी पूरी हुई, धीरे धीरे और विकास होगा ऐसा हम सब पूर्ववर्ती गांव वालों का मानना था, हमारे गांव में पहले पंचायती राज्य था अतः पंचायत घर का बनना तो लाजमी था, पूर्ववर्ती प्रधान एक सम्पन्न कृषक परिवार से थे कुछ सरकार द्वारा मिले अनुदान से कुछ लोगों के सहयोग से उन्होंने काफी काम कराया तभी लगातार बीस वर्षों तक वह निर्विरोध प्रधान होते आये थे। हमारे गांव में सभी धर्मों के लोग थे, हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख ईसाई जैन एक इंग्लैण्ड की वासी मेम भी थी। पूरा गांव उसे मेम के नाम से ही जानता था असली नाम कम से कम मुझे तो पता नहीं है। हरिजन भी थे, सफाई कर्मी भी थे कभी किसी के साथ न तो हमने कोई झगडा सुना न देखा।

कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हमारा गांव एक आदर्श गांव था। आपसी भाई चारा, सामाजिक सौहार्द, जाति पाँति के भेद नहीं, सभी अपनी अपनी सीमा पहचानते थे. अधिकतर लोग किसान ही थे और वही उनकी जीविका भी थी. गांव में एक गुरुद्वारा, एक मन्दिर, एक मस्जिद, एक गिरजा घर भी था, एक खैरती अस्पताल भी था जहाँ वैद्य सीताराम थे जवान के कड़वे थे लेकिन दवा सटीक देते थे, एक प्राइमरी पाठशाला भी थी, जो बाद में जूनियर हाई स्कूल बन गया था, लड़कियों और लड़कों को सामूहिक शिक्षा ही दी जाती थी कहने का मतलब की पूरे चैन और सुकून से गांव वाले रहते थे. लोहार, बर्ही, सुनार और छोटे मोटे किराने वाले थे मुख्य दो दुकानें ही थी एक लाला

आर.के.भारद्वाज

गोपी चन्द एंव उनके पुत्र किशोरी लाल दूसरी दुकान एक सिक्ख थे हरगोविन्द और उनके भाई दर्शन सिंह, हरगोविन्द सिंह थोड़े कांडिया क्रिस्म के थे लेकिन दर्शन सिंह बहुत ही हंसी मजाक करने वाले थे।

यह वर्णन तब का है जब स्व. जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधान मंत्री थे। बाद में गांव में और दुकानें भी खुली एक चायवाले की, एक साइकिल की मरम्मत करने वाले की, एक बड़ी दुकान जर्नल मरन्ट की आधुनिक डाक्टर भी आ गये एक होम्योपैथिक के डा. भी आ गये कहने का मतलब है कि हमारी छोटी मोटी आवश्यकतायें तो गांव से ही पूरी हो जाती थी. शेष के लिये पास का शहर था ही जो गांव से मात्र 6 किमी की दूरी पर था.

हमारे ही गांव में एक लड़का आया, वह कहाँ से आया कहाँ का था, उसकी जाति क्या थी, कितना पढा लिखा था कोई नहीं जानता लड़का बड़ा हंसमुख था न उसके पास कोई सामान, न कोई सम्बन्धी. बस ऐसे ही वह कब गया का ही आदमी बन गया कोई नहीं जानता बल्कि यों कहा जाये कि वह गांव वालों की आवश्यकता बन गया कोई नहीं जानता था. कई बार जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने टाल दिया बहुत ही जोर देने पर एक दिन बताया कि मुकसिंहि, अजीब सा नाम था लेने में परेशानी होती थी। एक दिन कुछ लोगों ने उससे उसकी जात पूछी उसने उल्टा सवाल कर दिया " आपकी क्या जाति है ?

सबने अपनी अपनी जाति बता दी. बस फिर जो तुममें सबसे बड़ी जाति का है वही मेरी भी। अजीब सा रहस्यमय आदमी था. न जाने कब गांव वालों ने ही उसका नाम मसखरा रख दिया। जिसने भी रखा बड़ा सोच समझ के रखा क्योंकि वह था भी बड़ा हंसोड़ बातों बातों में कब वह हंसी की बात निकाल लेता ये युक्ति उसी के बस की बात थी. लेकिन अपने निश्चल स्वभाव के कारण वह सभी का लोकप्रिय था, सभी उससे, उसके स्वभाव से प्रसन्न थे।

काम धन्धा तो वह कुछ करता नहीं था लेकिन पूरी बस्ती उसकी देनदार थी, अक्सर दुकानदार तो उसके ऋणी थे, किसी का माल उतरवा देता, किसी का माल चढ़वा देता पैसे लेने पर कहता " लाला न तो तुम कहाँ जा रहे हो न मैं, और फिर मैं कहाँ सभालता रहूँगा अपनी तिजोरी में मेरा माल भी रख लेना, और देखो गड़बड़ मत करना हमेशा याद रखना कि जहाँ पैसे रखे हैं वहाँ मेरे अधिक हैं तुम्हारे कम, जब ज़रूरत होगी ले लूँगा." लेने के मौके आते तो जितना जमा उससे कहीं कम।

कहानी

बंद घड़ी

○ आज बिस्तर की चार ठीक करते हुए दीवार पर लगी घड़ी की ओर नजर गयी। ना जाने कब से, कितने महनों से बंद पड़ी है घड़ी। मैंने नजर भर घड़ी को देखा और एक गहरी सांस लेकर रह गयी। वक्त जैसे ठहर गया है। वक्त जैसे वक्त न होकर घड़ी हो गया है, जब तक घड़ी चल रही थी वो भी चले रहा था। घड़ी रुकी तो वो भी ठहर गया। और बंद घड़ी में ठहरें वक्त की तरह ही ठहर गया है मेरा और असीम का रिश्ता। जैसे घड़ी के बारे में याद नहीं है कि वह किस दिन बंद पड़ी ऐसे ही याद नहीं असीम और मेरे बीच कब किस समय सब कुछ ठहर सा गया। कोई हलचल नहीं, उमंग नहीं, कोई लहर नहीं, उत्साह नहीं।

दूर धिंतित तब जैसे एक गहरी, उदास निःश्वास है। असीम का स्वभाव मुझे कभी समझ ही नहीं आया। अब तक उत्साह से भर कर, अपना समझकर उसके दिन के, मन के काम के कुछ हिस्से बांटना चाहती थी तो वह झल्ला जाता था। उसे लगता कि



मैं उसके जीवन में दखल अंदाजी कर रही हूँ। उसे कुदरत कर जासूसी कर रही हूँ उसकी निजता में व्यर्थ का हस्तक्षेप कर रही हूँ। मैं तो दंग रह गयी थी यह प्रत्यारोप सुनकर। पत्नी के आत्मवी स्नेह की, पति के साथ, उसके जीवन के साथ, उसके कार्य कलापों के साथ जुड़ने की एक प्राकृतिक स्वभाविकता, एक निश्चल प्रेम की भावना असीम को अपने जीवन में अनाधिकार हस्तक्षेप लगता है। असीम कभी समझ ही नहीं पाया कि दाम्पत्य सहज प्राकृतिक रूप से बहती हुई स्वच्छ धारा की तरह होता है।

उस पर यदि दुराव, छिपाव और शर्तों के बांध बना दिये जायें तो उसका प्रवाह रूक जाने से उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उस पर अलगवा

विनिता राहुरीकर

नहीं वरन् एक दर्भंध किले की तरह है। और इस किले की दीवारों में सेंध लगाना, या इसे जीत पाना असंभव है। बहुत वर्ष व्यर्थ कर दिये हैं अपने जीवन के मैंने इसी प्रयत्न में, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। आज फिर मैं का फोन आया था। समझा रही थी कि कुछ लोगों का मन कई खानों में विभक्त होता है और उनके कुछ खाने खुले होते हैं और कुछ पर ताले डले होते हैं। असीम का मन भी ऐसा ही है। खुले खानों की पहचान में ही खुश रह, बंद ताले तोड़ने का प्रयत्न मत कर। लेकिन क्या सच में ऐसे विभक्त होकर पूरी उम्र रहा जा सकता है? माँ-पिताजी का दाम्पत्य और आपसी संबंध देखते हुए बड़ी हुई। मन में जनम से ही एक सहज स्वाभाविक छाप अंकित थी।

विवाह मने जीवन के हर क्षण, हर रहस्य, हर सुख-दुःख और प्रत्येक पहलू का साथ, यही होता है जीवन साथी। हृदय में यही कोमल, सुवासित मगर मजबूत, दृढ़ माला लेकर मैंने असीम का वरण किया था। लेकिन कुछ ही महनों बाद असीम के व्यवहार के कारण उस माला के एक-एक फूल मुरझाते चले गये और जब तो घागा भी टूटने ही वाला है.

लघुकथा

विकास

○ जिस बस्ती में मैंने अपना झोंपड़ा बनाया है वह अभी विकास की भ्रूण अवस्था में है, न बिजली-पानी, न नाली न सड़कें, न फोन, न सीवर लाइन, लेकिन मुझे विश्वास था कि यह बस्ती जल्द ही न केवल विकास की चौनवावस्था को प्राप्त होगी बल्कि वृद्धा अवस्था को भी प्राप्त होगी, फिर एक दिन मेरी बस्ती में सड़कें बननी शुरू हो गयीं. पहले कच्ची, फिर रोडियाँ पड़नी शुरू हुईं, उसके बाद डामर की पक्की सड़क बन कर तैयार हो गई, एक सप्ताह के बाद नाली बनाने वाले आ गये, उन्होंने नाली बनाई, पक्की बनाई, बढ़िया बनाई, बेतरतीब बनाई, नाली की मिट्टी ने

सड़क को अपने गले लगा लिया, उसके बाद आए पानी के पाइप बिछाने वाले, बिजली वाले, उन्होंने जगह जगह से सड़क को काटकर अपना काम किया, बड़े बड़े गड्डों में सीमेंट के पाइप डाल कर खड़े किये, एक साल के बाद छोटे छोटे बल्ब जलने लगे।

इसके बाद ट्रकों में लदकर बड़े बड़े पाइप आये और उन्हें सड़कों के किनारे किनारे डाल दिया गया अब सीवर लाइन खुदने की बारी थी, कुछ दिन बाद सीवर लाइन वालों ने सड़क की मांग को बीच से उखाड़ना शुरू कर दिया, जब कि बस्ती अपनी नवयौवना अवस्था में थी, सीवर लाइन वाले अपना काम करके चले गये। अब सीवर लाइन बनी हुई दीख रही थी, सड़कें नाली तो पहले ही बन चुकी थी। अब मेरी बस्ती का पूरा विकास हो चुका है।



○ ओम्प्याकॉन, रूस के साखा गणराज्य के ओम्प्याकोन्स्की जिले में एक ग्रामीण इलाका (एक सेले) है, जो याना-ओइमार्कॉन हाइलैंड्स में, इंडिगिरका नदी के किनारे, टॉम्पोसे से 30 किमी (19 मील) उत्तर-पश्चिम में कोलिमा राजमार्ग पर स्थित है। ओम्प्याकॉन पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ मानव बस्ती है, जिसका औसत सर्दियों का तापमान लगभग 50 °C (58 °F) होता है। इस बस्ती का नाम ओम्प्याकॉन नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम कथित तौर पर इवन शब्द खेयम से आया है, जिसका अर्थ है "पानी का बिना जमा हुआ पेश; वह स्थान जहाँ मछलियाँ सर्दियों बिताती हैं"। हालाँकि, एक अन्य स्रोत बताता है कि इवन शब्द हेयम, एक गलत वर्तनी हो सकती है), जिसका अर्थ है "जमी हुई झील", हो सकता है कि यहीं से इसका नाम पड़ा हो। ओम्प्याकॉन के पास दो मुख्य घाटियाँ हैं। ये घाटियाँ शहर के अंदर हवा को फँसाती हैं और एक ठंडा वातावरण बनाती हैं। यहाँ का तापमान साल के अधिकांश समय बेहद ठंडा रहता है, और यहाँ वसंत और शरद ऋतु में अक्सर बर्फबारी होती है, लेकिन गर्मियों और सर्दियों में शायद ही कभी बर्फबारी होती है, क्योंकि सर्दियों में साइबेरियाई उच्च और गर्मियों में तापमान आमतौर पर 0 °C (32 °F) से ऊपर होता है। अगर यह 55 °C (67 °F) से ज्यादा ठंडा हो तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में ओम्प्याकॉन की आबादी में काफी कमी आई है। गांव की अधिकतम आबादी लगभग 2,500 थी, लेकिन 2018 में यह संख्या घटकर 900 से भी कम रह गई है।

शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में यौन रोग (सेक्स समस्या) पर सफल इलाज



सीताबर्डी टेम्पल बाजार स्थित शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में यौन रोग एवं सेक्स संबंधित सभी समस्याओं पर प्रभावकारी एवं सफल इलाज किया जाता है। रोज की जिंदगी में यौन समस्याएँ जैसे शीघ्रपतन बांझपन इत्यादि, के कारण सामाजिक एवं वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना तथा वैवाहिक कलह, कलह, का भी पडता समस्याओं समाधान है। रोज के जीवन में इनक्षकारणों तथा तत्वों के अभाव या कारणों से यह समस्या उत्पन्न होती है। इसका इलाज समोपचार औषधी चिकित्सा से संभव है। महाशक्ति कवच, रे-टोन सिरप, कप नाईट पावर इन दवाओं से इन समस्याओं का समाधान आयुर्वेदिक एजेंसी सीताबर्डी, टेम्पल बाजार रोड नागपुर में सफलतापूर्वक किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए 9112079000 / 8605245080 फोन पर संपर्क करें और आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान पाकर खुशहाल जीवन व्यतीत करें.

शिवशंकर आयुर्वेद एजन्सी

सीताबर्डी स्थित शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अथवा क्लिनिक में 9112079000 / 8605245080 इन दूरवार्ती क्रमांकों पर संपर्क स्थापित करें.



चिमूर की व्यवसायी महिला नागपुर में लापता

> सात दिन बाद भी पुलिस की धीमी जांच

चिमूर. शहर की व्यवसायी महिला खगोलवार 26 नवंबर को सुबह खरीदारी के लिए नागपुर गईं और दोपहर 12.30 बजे जब वह नागपुर के इतवार पहुंची तो वापस चिमूर नहीं लौटीं. यह घटना उसी दिन शाम को उजागर हुई. उक्त व्यवसायी महिला का नाम अरुणा अभय काकडे 37 है. संबंधित महिला नूतन आदर्श कालनी चिमूर की निवासी है. इसकी रिपोर्ट नागपुर पुलिस स्टेशन और चिमूर पुलिस स्टेशन को दी गई. लेकिन पुलिस जांच धीमी गति से चल रही है. जांच तेज गति से करने की मांग शहर के व्यापारिक महिलाओं, महिला मंडल, मित्र मंडल और व्यापार मंडल ने की है.



अवैध रेती परिवहन में ट्रैक्टर जब्त

> तहसीलदार कौटकर की कार्रवाई वररा.

चिखले डेढ़ वर्ष से रेती घाट की निलामी नहीं होने से तथा बहारी जिले की मंहंगी रेत मिलने से कुछ छोटे मोटे रेत तस्क़र चुनाव में व्यस्त महसूल अधिकारियों का फायदा उठाते हुवे रेत तस्क़रों ने अवैध रेत तस्क़रों चालू की थी. इनपर लगाम लगाने हेतु स्वयं तहसीलदार योगेश कौटकर आधी रात को करंजी रेत घाट, तुलना रेत घाट, खांबाडा,

की दुकान है. जो पांच साल से शहर के मुख्य रास्ते पर सातनाला के पास है. हर बार की तरह हरे में या पंधरा दिन में व्यावसायी महिला अरुणा नागपुर में खरेदी के लिए जाती थी. सात दिन पहले 26 नवम्बर को सुबह दुकान के सामान खरेदी करने गई थी. वह महिला उस दिन घर नहीं लौटी. अरुणा की तलाश परिवार के नागरिकों ने की लेकिन वह नहीं लौटी. इसलिए नूतन आदर्श कालनी की महिला पुरुष, मैत्रीनी और व्यापारी संघ ने चिमूर पुलिस जांच धीमी गति से चल रही है. जांच तेज गति से करने की मांग शहर के व्यापारिक महिलाओं, महिला मंडल, मित्र मंडल और व्यापार मंडल ने की है.

देवांश जनरल एंड लेडीज कॉर्रर नामक लापता व्यवसायी महिलाओं को तलाश कर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाने की मांग की गई. जापन की प्रति विधायक बंटी भांगड़िया, जिला पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी को दी गई है.

सुरला के साथ ही तहसिल के अन्य रेत घाट पर अपने टीम के साथ जाल बिछाकर 3 रेत भरे ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर उन्हें जब्त कर तहसिल कार्यालय में जमा कर दिया. इनपर लगाम साडेतीन लाख की दंडात्मक कार्रवाई की. इस कार्रवाई से रेत तस्क़रों में हड़कम मचा है. रेत घाट नीलाम न होने से चोरी की रेत के ऊंचे दाम होने से अनेक निर्माण कार्य प्रभावित हुवे है. इसका असर निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूर पर भी हो रहा है. इन सारी समस्याओं का हल निकालने रेत घाट नीलाम करने की मांग जनता कर रही है.

जिला चंद्रपुर-गढ़चिरोली

शहर को स्वच्छ रखकर नागरिकों की समस्या पहले हल करें

चंद्रपुर, सुनील तावडे

भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक किशोर जोरगेवार ने चंद्रपुर पहुंचते ही कार्यालय में जनसंपर्क किया और नागरिकों की समस्याएं जानी. जैसे ही उन्हें मनपा से जुड़ी समस्या होने का ज्ञान होने पर उन्होंने तत्काल मनपा आयुक्त पालीवाल को अपने कार्यालय बुलाकर शहर को साफ-सुथरा रखने और नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिये.

आशावाद देकर लगातार दूसरी बार विधायक के लिए जीत दिलाई है. चंद्रपुर में कई विकास कार्य होने हैं. पिछले पांच वर्षों में जो महत्वपूर्ण कार्य अचूक रह गए हैं उन्में तेजी लानी होगी. आपके वोटों के आशावाद से हम विकास की नींव मजबूत करेंगे, ऐसा आश्वासन नवनिर्वाचित विधायक किशोर जोरगेवार ने इस अवसर पर दिया.



कार्यालय पहुंचे. इस मौके पर कई सामाजिक संगठनों, विभिन्न समाजों और संस्थाओं की ओर से उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पडवकर को बीजेपी उम्मीदवार किशोर जोरगेवार ने 22 हजार से ज्यादा वोटों

से हराया था. निर्वाचित होने के बाद पार्टी नेताओं के आदेशानुसार उन्होंने मुंबई में प्रवेश किया था. विधानसभा क्षेत्र में लौटते ही वे जनसंपर्क कार्यालय आये और नागरिकों की समस्याएं सुनीं. शहर में साफ-सफाई व जलापूर्ति की कमी जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाये. इसके बाद विधायक किशोर जोरगेवार ने मनपा आयुक्त को फोन किया और आयुक्त को तत्काल उपाययोजना उठाने के निर्देश दिए.

चुनाव प्रचार के दौरान नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नागरिकों से कई शिकायतें मिलीं. उन शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया, लेकिन ऐसी शिकायतें दोबारा नहीं होनी चाहिए. नगर निगम प्रशासन को ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए और शहर को साफ रखना चाहिए. कई इलाकों में लाइटें बंद हैं. इसलिए, क्षेत्रों में स्थायी उपाय किए जाने चाहिए. साथ ही क्षेत्र में समान जल आपूर्ति के लिए हर बेहतर योजना बनाई जानी चाहिए ऐसे सुझाव विधायक जोरगेवार ने दिए.

विधायक जोरगेवार की मनपा आयुक्त को निर्देश

धान के ढेर को आग

पोंधुर्णा.

तहसील के सेलूर नागरेड्डी के गांव के पास खेत में रखे धान के ढेर को आग लगने से वह जलकर पूरी तरह से खाक हो गया. यह घटना रविवार की दोपहर घटी. सुनिल मारोती कोतपल्लीवार नामक किसान का इससे लाखों का नुकसान हुआ है. पोंधुर्णा तहसील में सेलूर नागरेड्डी के सुनील कोतपल्लीवार के सर्वे नंबर 190 में 1 हेक्टर 14 आर और ताराबाई मारोती कोतपल्लीवार के नाम सर्वे नंबर 188/1 में 52 आर खेत है और इन दोनों खेतों में धान की कटाई कर कुछ दिन पहले सर्वे नंबर 190 में धान के ढेर लगाए थे. दोन दिन बाद धान निकालने और धान की बिक्री करने की तैयारी कोतपल्लीवार ने की थी. इसी बीच 1 दिसंबर को

किसान का लाखों का नुकसान सेलूर नागरेड्डी की घटना



करीब तीन बजे खेत में धान के ढेर को आग लग गई. इसमें जय श्री राम प्रजाति के धान के कुल 80 बोरी, औसतन 75 क्विंटल धान निकलनेवाला था. इससे करीब लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे उनके ऊपर बड़ा आर्थिक संकट आ गया है. किसान के सामने पूरे साल परिवार का भरण-पोषण कैसे करें यह

दो ट्रैक्टर सहित 130 ब्रास का अवैध रेत भंडार जब्त

> राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई

ब्रम्हपुरी.

रेत तस्क़रों ने ब्रम्हपुरी तालुका के तोरगांव (बु.) क्षेत्र के वन विभाग क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया था. इसकी जानकारी जैसे ही तहसीलदार सतीश मासाल को मिली. 1 दिसंबर को अवैध रेतभंडारों पर छापेमारी की गयी और 130 ब्रास रेत भंडारों के साथ दो ट्रैक्टर जब्त किये गये. इस कार्रवाई से तालुका के रेत तस्क़रों को झटका लगा है. ब्रम्हपुरी तालुका की रेती सर्वत्र प्रसिद्ध है. इसलिए इस रेत की मांग अधिक है. लेकिन, रेत घाट की नीलामी नहीं होने से कई रेत चोर सक्रिय हो गये हैं. जब राजस्व अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के काम में

दो ट्रैक्टर सहित 130 ब्रास का अवैध रेत भंडार जब्त

> राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई

ब्रम्हपुरी.

रेत तस्क़रों ने ब्रम्हपुरी तालुका के तोरगांव (बु.) क्षेत्र के वन विभाग क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया था. इसकी जानकारी जैसे ही तहसीलदार सतीश मासाल को मिली. 1 दिसंबर को अवैध रेतभंडारों पर छापेमारी की गयी और 130 ब्रास रेत भंडारों के साथ दो ट्रैक्टर जब्त किये गये. इस कार्रवाई से तालुका के रेत तस्क़रों को झटका लगा है. ब्रम्हपुरी तालुका की रेती सर्वत्र प्रसिद्ध है. इसलिए इस रेत की मांग अधिक है. लेकिन, रेत घाट की नीलामी नहीं होने से कई रेत चोर सक्रिय हो गये हैं. जब राजस्व अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के काम में

दो ट्रैक्टर सहित 130 ब्रास का अवैध रेत भंडार जब्त

> राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई

ब्रम्हपुरी.

रेत तस्क़रों ने ब्रम्हपुरी तालुका के तोरगांव (बु.) क्षेत्र के वन विभाग क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया था. इसकी जानकारी जैसे ही तहसीलदार सतीश मासाल को मिली. 1 दिसंबर को अवैध रेतभंडारों पर छापेमारी की गयी और 130 ब्रास रेत भंडारों के साथ दो ट्रैक्टर जब्त किये गये. इस कार्रवाई से तालुका के रेत तस्क़रों को झटका लगा है. ब्रम्हपुरी तालुका की रेती सर्वत्र प्रसिद्ध है. इसलिए इस रेत की मांग अधिक है. लेकिन, रेत घाट की नीलामी नहीं होने से कई रेत चोर सक्रिय हो गये हैं. जब राजस्व अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के काम में

पाटिल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ब्रम्हपुरी तालुका तहसीलदार सतीश मासाल, नायब तहसीलदार आशीष तालेवार, ग्राम राजस्व अधिकारी हिमांशु पाजनकर, घनश्याम राऊत, भूपेन्द्र गौरे, स्वपिल इसड आदि ने तोरगांव क्षेत्र में वन विभाग क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित रेत स्टॉक पर छापेमारी कर 130 ब्रास अवैध रेत स्टॉक जब्त किया गया. घटना स्थल पर रेत भंडारण कर रहे दो ट्रैक्टरों में अवैध रेत पाए जाने के कारण ट्रैक्टरों को जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई हेतु तहसील कार्यालय में जमा करा दिया गया है. राजस्व विभाग द्वारा अवैध रेत स्टॉक, अवैध परिवहन, अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई करने पर राजस्व विभाग को हर जगह बधाई दी जा रही है। राजस्व विभाग की कार्रवाई से रेत तस्क़रों के होश उड़ गये हैं.

मृतक कामगारों के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दे

> विधायक अडबाले का कंपनी प्रबंधन को निर्देश

चंद्रपुर। ताडाली एमआईडीसी स्थित ओमेट वेस्ट लिमिटेड(पुराने सिद्धबली इस्पत लिमिटेड) इस कंपनी में 13 अक्टूबर 2024 को अजय रविंद्र राम नामक कामगार का 200 किलोग्राम स्टील स्क्रैप गिरने से मृत्यु हो गई. कंपनी प्रबंधन ने उक्त कामगार के परिजनों को बिना कोई मुआवजा दिये शव को उसके पैतृक गांव भेज दिया. साथ ही पांच महीने पहले इसी कंपनी में श्यामसुंदर टेंगेने नामक कर्मचारी की मौत हो गई थी. उन्हें योजना के मुताबिक पूरी मदद भी नहीं दी गई. इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक सुधाकर अडबाले ने सहायक कामगार आयुक्त के कक्ष में कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि दोनों मृत श्रमिकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए. ओमेट वेस्ट लिमिटेड (पुरानी सिद्धबली इस्पत लिमिटेड) कंपनी में पिछले महीने हुई घटना के बाद विधायक सुधाकर अडबाले ने कंपनी

को उसके पैतृक गांव भेज दिया. साथ ही पांच महीने पहले इसी कंपनी में श्यामसुंदर टेंगेने नामक कर्मचारी की मौत हो गई थी. उन्हें योजना के मुताबिक पूरी मदद भी नहीं दी गई. इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक सुधाकर अडबाले ने सहायक कामगार आयुक्त के कक्ष में कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि दोनों मृत श्रमिकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए. ओमेट वेस्ट लिमिटेड (पुरानी सिद्धबली इस्पत लिमिटेड) कंपनी में पिछले महीने हुई घटना के बाद विधायक सुधाकर अडबाले ने कंपनी



का दौरा किया और कई गंभीर मुद्दों का अवलोकन किया. विधायक सुधाकर अडबाले ने उद्योग एवं श्रम विभाग के प्रमुख सचिव को एक जापन के माध्यम से मांग की है कि मृतक श्रमिक को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का

मामला दर्ज कर कंपनी की गहन जांच की जाए. इसके बाद सहायक श्रमायुक्त चंद्रपुर ने विधायक सुधाकर अडबाले की उपस्थिति में कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक की. विधायक अडबाले ने पूछा कि कंपनी के मृत कर्मी अजय रविंद्र राम को आर्थिक सहायता दिलाते

के लिए क्या कार्रवाई की गयी. इसपर फिलहाल श्रमिक के वारिस को 2 लाख रुपये दे दिए गए हैं और बाकी मुआवजा राशि नियमानुसार दी जाएगी. इसके अलावा जून माह में उक्त कंपनी में श्यामसुंदर टेंगेने नामक कर्मी की मौत हो गयी थी. कंपनी प्रबंधन की ओर से इस बात पर सहमति बनी कि वारिसों को 4.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 30 लाख दे दिए गए हैं और कंपनी ने अब तक 1.5 लाख का भुगतान क्यों नहीं किया है यह पूछा गया. कंपनी मैनेजर ने कहा कि बाकी रकम नियमानुसार दी जाएगी. इसके साथ ही उक्त

कंपनी का स्टूचरल ऑडिट, कंपनी में श्रमिकों को सुरक्षा के लिहाज से दी जाने वाली सुविधाएं, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, कृषि फसलों को नुकसान, प्रवासी श्रमिकों का पुलिस सत्यापन, श्रमिकों को नियमित वेतन समेत अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई. इन मामलों की विस्तृत जानकारी सहायक श्रमायुक्त को देनी चाहिए. ऐसा विधायक सुधाकर अडबाले ने कहा. साथ ही विधायक अडबाले ने कहा कि इसी विषय पर जिलाधिश, फैक्टरी निरीक्षक, सहायक श्रमायुक्त के साथ कंपनी प्रबंधन की बैठक की जायेगी.

नक्सल सप्ताह के दौरान महिला माओवादी ने किया गढ़चिरोली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण

महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया था कुल 2 लाख रुपये का इनाम

गढ़चिरोली. वर्ष 2005 से सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण योजना के कारण और हिंसा के जिवन से तंग आकर वरिष्ठ माओवादीयों समेत कई कट्टर माओवादीयों ने पुलिस के वन क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया है। साथ ही, आत्मसमर्पणित माओवादीयों के लिए पुलिस बल द्वारा चलाए जाने वाले नक्सल योजना के चलते अबतक कुल 679 माओवादीयों ने गढ़चिरोली पुलिस बल के सामने आत्मसमर्पण किया है। आज तारिख 02 दिसंबर 2024 को तारा ऊर्फ शारदा ऊर्फ ज्योती दस्सा कुळ्मेथे, उम्र 28 साल, निवासी नैनेर, तह. अहोरी, जि. गढ़चिरोली नामक महिला माओवादीने नक्सल सप्ताह के दौरान गढ़चिरोली पुलिस बल और सिआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया है। नाम- तारा ऊर्फ शारदा ऊर्फ ज्योती दस्सा कुळ्मेथे, दलम में कार्यकाल वर्ष 2016 में अहोरी दलम में सदस्य पद पर भर्ती होकर वर्ष 2018 तक सक्रिय थी। वर्ष 2018 से आज तक भामरागढ़ दलम में कार्यरत थी। कार्यकाल में किए अपराध मुठभेड 08, वर्ष 2016 कवठाराम वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2017 शेडा-फिष्टापुर वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2017 आशा-नैनेर वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2017 मोरमेडा वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2020 आलदंडी वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2020 येदठळ्मी वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2021 कालूर माड क्षेत्र (छत्तीसगढ़) वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2023 हिक्कर वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2023 हिक्कर वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड में शामिल। वर्ष 2021 में मौजा कोटी गाव के एक निर्दोष व्यक्ति के हत्या में वह शामिल थी। वर्ष 2023 में मौजा मिडदापल्ली गाव के एक निर्दोष व्यक्ति के हत्या में वह शामिल थी। वर्ष 2024 में मौजा ताडगाव गाव के एक निर्दोष व्यक्ति के हत्या में वह शामिल थी। वर्ष 2022 में कोपेवंचा राजनिम (खां) में हुए डकैती में वह शामिल थी। आत्मसमर्पण के कारण माओवादी मने दिन-रात वन मे घुमते हुए जिवन बिताना पडता है, अगर किसी को स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हुई तो उसपर ध्यान नहीं दिया जाता। दलम के वरिष्ठ माओवादी द्वारा महिलाओ के साथ भेदभाव किया जाता है। दलम के वरिष्ठ नेता कहते हैं की, आंदोलन एवं लोगो के लिए पैसा इकठ्ठा करना पडता है। वास्तव में इकठ्ठा किया गया पैसा वरिष्ठ माओवादी लोगो के विकास कार्य के लिए न करते हुए वही पैसा स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। वरिष्ठ माओवादी नेता केवल अपने फायदे के लिए गरिब आदिवासी युवाओ का इस्तेमाल करते हैं। वरिष्ठ माओवादी नेता केवल पुलिस मुखबि्र होणे के संदेह पर हमारे ही भाई-बहनो की हत्या करणे को कहते हैं। मुठभेड के दौरान पुरुष माओवादी भाग जाने में सफल हो जाते हैं, पर महिला मारे जाते हैं। सरकार द्वारा घोषित इनाम महाराष्ट्र सरकारने तारा ऊर्फ शारदा ऊर्फ ज्योती दस्सा कुळ्मेथे पर कुल 2 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया था।आत्मसमर्पण के बाद सरकार की ओर मिलने वाले इनाम आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वसन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तारा ऊर्फ शारदा ऊर्फ ज्योती दस्सा कुळ्मेथेको कुल 4.5 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया है। गढ़चिरोली पुलिस बल द्वारा चलाए जाने वाले प्रभावी माओवादी विरोधी अभियान के कारण और सरकारने माओवादीयों को आत्मसमर्पण का सुहरा अवसर उपलब्ध करा देने के कारण सन्मानपुर्वक जीवन बिताने के लिए



वर्ष 2022 अबतक कुल 31 कट्टर माओवादीयों ने आत्मसमर्पण किया है। उक्त माओवादी के आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लाने की कार्यवाही श्री. संदीप पाटील, विशेष पुलिस महानिरीक्षक (नक्सल विरोधी अभियान) नागपुर, श्री. अंकित गौयल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़चिरोली परिक्षेत्र, श्री. अजय कुमार शर्मा, पुलिस उप-महानिरीक्षक (अभियान) सीआरपीएफ, पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, शंभु कुमार, कर्मांडण्ट 09 बटा. सिआरपीएफ और सुर्मात वर्मा, उप-कर्मांडण्ट इंटर सिआरपीएफ के मार्गदर्शन में पुरी की गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने आवाहन किया है की, पुलिस बल विकास कार्यों मे बाधा डालने वाले माओवादीयो के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, वही गढ़चिरोली पुलिस बल उन लोगो की मदद करेगी जो विकास के मुख्य धारा मे शामिल होने और लोकतंत्र में सम्मान जनक जीवन जीने के लिए इच्छुक है, उन्हे गढ़चिरोली पुलिस बल पुरा सहयोग करेगा। इस लिए राह भटके हुए माओवादी मुख्यधारा मे शामिल होकर शांततापुर्ण जीवन व्यतीत करें।

चंद्रपुर महानगर पालिका स्काॅच पुरस्कार से सम्मानित

> वर्षा जल संचयन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता

चंद्रपुर.

चंद्रपुर नगर निगम को स्काॅच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और शहर में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन करके शहर के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। नगर निगम आयुक्त विपिन पालीवाल, अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल और उपायुक्त मंगेश खवले ने दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में स्काॅच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर और उपाध्यक्ष गुरुशरण सिंह धंजल से पुरस्कार स्वीकार किया। इस अवसर पर आयुक्त विपिन पालीवाल ने चंद्रपुर शहर में वर्षा जल संचयन के लिए सहयोग करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को धन्यवाद दिया. चंद्रपुर नगर निगम ने वर्षा जल संचयन के बारे में काफी जन जागरूकता पैदा की है। संचयन के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले 31 जलमित्रों को नियुक्त किया गया और पुरस्कारों की घोषणा सिल्वर जलमित्र, गोल्डन जलमित्र, डायमंड जलमित्र और नगर जलमित्र के रूप में की गई।



वार्डों में घर-घर जाकर पंचें बांटे गए और कुएं और बोरवेल वाले घरों को जुमनि के नोटिस भी जारी किए गए। नगर निगम द्वारा फसल कटाई के लिए घर की छत के क्षेत्रफल के अनुसार 5, 7 और 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है और अगले 3 वर्षों के लिए संपत्ति कर में 2 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। नए निर्माण की अनुमति चाहने वाले भवन स्वामियों को वर्षा जल संचयन करने के लिए बाध्य किया गया तथा अन्य सभी माध्यमों से जनजागरूकता फैलाई गई तथा नगर निगम के इन प्रयासों को उक्त संस्था द्वारा संज्ञान में लिया गया। स्काॅच ग्रुप 1997 से भारत में एक अग्रणी पूर्ण सेवा परामर्श

फर्म है। फर्म की शोध रिपोर्ट और अनुसंधानों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। संस्थान को शासन, वित्त, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग नागरिकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त है। इस संस्थान के कार्य को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए एक मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्काॅच ग्रुप द्वारा 2003 में स्थापित, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए ठोस कार्य और साक्ष्य का उपयोग करके समाज में उसके योगदान का आकलन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य व्यक्तियों और संगठनों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मान्यता दी जाए।

सबसे आगे बैठेंगे पीएम मोदी

प्रियंका गांधी वाड़ा को मिली सीट नंबर 517 | लोकसभा में सांसदों के लिए सीटों का हुआ आवंटन

नई दिल्ली।

लोकसभा में सांसदों के लिए सीटों का आवंटन पूरा हो चुका है। ताजा व्यवस्था के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले की तरह 1 नंबर सीट आवंटित की गई है। जबकि, संसद की नई सदस्य वायनाड से उपचुनाव जीतने वाली प्रियंका गांधी वाड़ा को 517 नंबर की सीट आवंटित की गई है। विपक्षी दलों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सबसे पहली पंक्ति में



होंगे। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय



मंत्री नितिन गडकरी को पहले दूसरे कॉलम में डिवायन नंबर 58 आवंटित किया गया था, लेकिन अब उन्हें गृह

विपक्ष दलों के नेता कहां बैठेंगे

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी दलों की आगे की पंक्ति में सीट संख्या 355 पर बैठेंगे। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय यादव के बगल में बैठेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को 280, कल्याण बनर्जी को 281 और सींगत रॉय को 284 नंबर की सीट दूसरी पंक्ति में आवंटित हुई है। द्रमुक नेता टी आर बाबू और ए राजा को भी आगे की पंक्ति में सीटें आवंटित की गई हैं।

मंत्री अमित शाह के बगल वाली सीट संख्या चार दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री के बगल वाली डिवायन सीट संख्या दो मिली है। मोडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,

कांग्रेस महासचिव केशी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के पास सीट नंबर 497 दी गई है। जबकि, फैजाबाद सांसद अवधेस प्रसाद को दूसरी रो में जगह दी गई है। अब वह डिंपल

यादव की सीट 358 के बगल में 357 पर बैठेंगे। प्रियंका गांधी वाड़ा के पास वाली सीटों पर कांग्रेस सांसद अर्धु प्रकाश और असम से प्रद्युत बोरदोलोई मौजूद होंगे।

गुलमर्ग में हुई बर्फबारी

दक्षिण भारत के 3 राज्यों में भारी बारिश जारी



नई दिल्ली।

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में सोमवार रात से बर्फबारी जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में पारा 10° तक पहुंच गया। दक्षिण भारत के 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फेंगल तूफान के कारण भारी बारिश हो रही है। पिछले 4 दिन में तमिलनाडु में तूफान से 12 मौतों का दावा किया गया है।

इस बार की सर्दियों में शीतलहर वाले दिन यानी कोल्डवेव डेज कम होंगे। दिसंबर से लेकर जनवरी-फरवरी तक देश के कई हिस्सों में तापमान भी सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को टंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मुआस विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड,

बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले तीन महीने के दौरान कोल्ड वेव डेज 2 से 6 दिन कम हो सकते हैं। वहीं, दिसंबर में पहाड़ी राज्यों को छोड़कर बाकी जगह कोल्डवेव डेज की संभावना बेहद कम है। बर्फबारी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी कम होगी। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। यहां मंगलवार सुबह 9 बजे तक एक्वशूअई 308 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय पर बर्फ से ढंका क्षेत्र इस साल फरवरी की तुलना में 32% तक घट गया है। साथ ही मानसून में इस बार 108% बारिश हुई थी। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से भी इस बार कड़के की टंड पड़ने की संभावना कम है। पिछले साल यानी 2023 में स्नो कवर एरिया 40% था और मानसूनी बारिश 94% ही हुई, जिससे कड़के की टंड पड़ी थी।

ऑपरेशन के लिए तैयार आईएनएस विक्रांत



समुद्री इतिहास में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत कोच्चि।

दक्षिणी नौसेना कमान के पर्यटन ऑफिसर कर्माडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने कहा कि भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ने पूर्ण परिचालन स्थिति हासिल कर ली है। इसके पहले आईएनएस ने इस साल अपनी अंतिम परिचालन मंजूरी हासिल की थी। कोच्चि में नौसेना के जहाज आईएनएस शार्दूल पर मीडिया से बातचीत में श्रीनिवास ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं के पूरा होने और जहाज के बेड़े के एकीकरण के साथ आईएनएस विक्रांत अब पूरी तरह से चालू हो चुका है। वह पश्चिमी बेड़े के तहत काम कर रहा है। श्रीनिवास ने इस बात पर जोर दिया कि देश और नौसेना के लिए गौरव का प्रतीक यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के सभी अभियानों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में

पुरी तरह सक्षम है। पोत को 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेना में शामिल किया गया था। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (डब्ल्यूडीबी) ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से किया गया है। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। अत्याधुनिक स्वचालन सुविधाओं से युक्त इस जहाज में लगभग 2,200 कंपार्टमेंट हैं। जिन्हें महिला अधिकारियों और नाविकों समेत लगभग 1,600 लोगों के चालक दल को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मिग-29के लड़ाकू जेट, कामोव-31 हेलीकॉप्टर, एमएच-60आर मर्कटरी-रोल हेलीकॉप्टर, और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तैनात हैं।

'बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जाए'

सीएम ममता ने केंद्र को दिया प्रस्ताव

कोलकाता। बांग्ला की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में मौजूद हालात के मद्देनजर वहां विशेष शांति सेना भेजी जाने की वकालत की है। सोमवार को विधानसभा में बोलते हुए ममता ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह बांग्लादेश मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में उठाए। उन्होंने केंद्र से वहां शांति सेना भेजे जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की अपील की। ममता ने कहा कि विशेष शांति सेना किसी देश को संघर्ष के रास्ते से वापस शांति के रास्ते पर लाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो संघर्ष का माहौल बन गया है, उसे संभालने की क्षमता मोहम्मद युसुफ की अंतरिम सरकार के



पास नहीं है। परिणामस्वरूप, वहां संयुक्त राष्ट्र की विशेष शांति सेना को तुरंत तैनात करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि बांग्लादेश में जिन भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें वापस लाकर बांगाल में रहने की व्यवस्था करने के लिए वह तैयार है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनके भोजन में कोई समस्या नहीं होगी।

ममता ने बांग्लादेश की घटना पर केंद्र सरकार की भूमिका पर नाराजगी भी व्यक्त की। हिंदू नेता की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए ममता ने कहा कि 10 दिन हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार पूरे मामले पर चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा हर दिन केवल मार्च कर रही है। हमें भी विरोध करने का अधिकार है। लेकिन मैं बांग्लादेश मामले में केंद्र के परामर्श को मानकर

पीएम द्वारा बांग्लादेश मुद्दे पर बयान देने की मांग

ममता ने बांग्लादेश मुद्दे पर मोदी से संसद में बयान देने की मांग भी उठाई है। उनके मुताबिक संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए पीएम को बांग्लादेश के बारे में बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वह कूटनीतिक या अन्य कारणों से बयान नहीं देते हैं तो विदेश मंत्री एन जयशंकर को बांग्लादेश के हालात पर संसद में बयान देना चाहिए।

ही चलीगी। बांग्लादेश को लेकर ज्यादा कुछ कहना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

गगनयान मिशन पर बड़ी खुशखबरी



नई दिल्ली। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इतिहास रचा था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। साथ ही चांद पर मानवरहित यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश। चंद्रयान-3 के बाद इसरो आगामी वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में कई मिशन लॉन्च करने वाला है। इसमें चंद्रयान-4 और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के साथ गगनयान मिशन भी है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने सोमवार को भारत के गगनयान मिशन पर बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान 2026 के अंत तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। एस सोमनाथ ने कहा कि गगनयान मिशन के तहत रॉकेट की पहली मानवरहित परीक्षण उड़ान अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जाएगी। बता दें कि गगनयान परियोजना का

उद्देश्य तीन दिवसीय मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजकर भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसके बाद, उन्हें समुद्र में सुरक्षित उतारकर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। यदि 90 अरब रुपये की लागत वाली यह स्वदेशी अंतरिक्ष परियोजना सफल हो जाती है, तो भारत सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। आईआईटी-गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए एस सोमनाथ ने कहा, हम पिछले चार वर्षों से गगनयान परियोजना पर काम कर रहे हैं। हमारा रॉकेट पूरी तरह से तैयार है। टेस्टिंग लॉन्चिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जाएगी। हम इसे इस साल दिसंबर में करना चाहते थे, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है।

एशिया में पहली जल परिवहन सेवा शुरू

श्रीनगर।

आपने उबर की टैक्सी, ऑटो या बाइक सर्विस का लुफ्त लिया होगा। दिग्गज टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी ने भारत में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। इस सर्विस का नाम है- उबर शिकारा। यह सर्विस आपको अभी कश्मीर में ही मिलेगी। अगर आप कश्मीर की वादियों का मजा उठाना चाहते हैं और फेमस डल झील घूमना चाहते हैं, तो कंपनी ने डल झील में घूमने के लिए शिकारा सर्विस शुरू की है। उबर इंडिया एवं दक्षिण एशिया के अध्यक्ष प्रबजोत सिंह ने सोमवार को बताया कि उबर के ऐप के जरिये अब श्रीनगर में डल झील पर शिकारे की बुकिंग की जा



सकेगी। कंपनी ने एशिया में अपनी तरह की यह पहली सेवा शुरू की है। सिंह ने कहा, उबर शिकारा यात्रियों को शिकारा की सवारी के लिए एक

सहज अनुभव देने के लिए प्रौद्योगिकी तथा परंपरा को मिलाने का हमारा प्रयास है। हमें कश्मीर के लुभावने परिदृश्य में पहुंच बढ़ाने और पर्यटन

को बढ़ावा देने वाली यह सेवा प्रदान करने पर गर्व है। उबर के प्रवक्ता ने एपि की कि भारत में उबर की जल परिवहन सेवा एशिया में भी अपनी तरह की पहली सेवा है। कंपनी इटली के वेनिस सहित कुछ यूरोपीय देशों में जल परिवहन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। भारत में कंपनी ने शुरुआत में सात शिकारा को शामिल किया है और सेवा की लोकप्रियता के आधार पर धीरे-धीरे बेड़े का विस्तार करने की योजना बना रही है। उबर यूजर्स सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिकारा बुक कर सकेंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि उबर अपने शिकारा भागीदारों से कोई शुल्क नहीं ले रही है और पूरी राशि उन्हें दे दी जाएगी।

बांग्लादेश ने भारत के राजदूत को किया तलब

ढाका।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं के बीच मोहम्मद युसुफ सरकार ने अगरतला मामले में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। अगरतला में बीते दिनों बांग्लादेश के राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। बांग्लादेश सरकार ने इस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज किया है। अंतरिम सरकार में कानूनी मामलों के सलाहकार ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि भारत को समझना चाहिए कि यह शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है। दरअसल मामला यू है कि हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी



अगरतला में सोमवार को हजारों की संख्या में लोगों ने व्यापक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कथित तौर पर घुस गए और कथित तौर पर तोड़फोड़ की। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बहुत खेदजनक बताया है। बांग्लादेश राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ करने के आरोप में सात लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सात पुलिसकर्मीयों पर लापरवाही के आरोप में एक्शन लिया जा चुका है।

मंगलवार को भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच खबर आई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापक और बहुआयामी संबंध हैं, जिन्हें किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं किया जा सकता।

जाते-जाते बाइडेन ने यूक्रेन पर उड़ेली खजाना

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले महीने खत्म हो रहे अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में यूक्रेन को 725 मिलियन डॉलर यानी करीब 6139 करोड़ रुपये की बड़ी सैन्य मदद देने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य युद्ध के मैदान में न केवल रूस का मुकाबला करना है बल्कि क्रीम को रणक्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस सहायता पैकेज के साथ अमेरिका यूक्रेन को कई किस्म के हथियार भी उपलब्ध करा रहा है, जिसमें कई ड्रोन रोधी सिस्टम, हार्ड जोम्बिटली आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और एंटी पैर्सनल लैंड माइंस भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा घातक हथियार सौंपने के बाद चर्चा का बाजार गर्म है और आर्मा टैकिंगल मिसाइल सिस्टम को लेकर कई किस्म की अटकलें लगाई जा रही हैं।

अल-जोलानी की दहशत से घुटनों पर सीरि

सीरिया। मिडिल ईस्ट में सीरिया के बड़े शहर अलेप्पो पर सरकार विरोधी विद्रोहियों हयात तहरीर अल-शाम ने कब्जा कर लिया है। इन विद्रोहियों ने एक हफ्ते से भी कम समय में सीरियाई सेना को घुटनों पर ला दिया। सीरिया को इन विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए रूसी सेना की मदद लेनी पड़ी, लेकिन फिर भी पलड़ा विद्रोहियों का ही भारी लग रहा है। तहरीर अल-शाम सीरिया में इस्लामिक कानून चाहता है, इसका अभी सीरिया से बाहर ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। आठ साल पहले सीरिया को इसे हराने के लिए रूस और ईरान की मदद लेनी पड़ी थी। इजरायल भी इसे आतंकी ग्रुप को अपने लिए खतरा मानता है। ये आतंकी यद्दियों को अपना दुश्मन मानते हैं। इस लिहाज से सीरिया में इनकी बढ़त इजरायल के लिए खतरे की घंटी भी है। इन विद्रोहियों का सरदार है- अबू मुहम्मद अल-जोलानी। अबू मुहम्मद अल-जोलानी के सिर पर अमेरिकी सरकार ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है।

संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय की निदेशक आरती होला मैनी का कहना है कि अंतरिक्ष यातायात समन्वय में देरी करने का समय नहीं है। अंतरिक्ष में इतनी सारी वस्तुएं भेजी जा रही हैं कि हमें अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इसका मतलब है कि टकराव से बचने के लिए ऑपरेटर्स के बीच सूचना साझा करना जरूरी है।

पृथ्वी की निचली कक्षा में 14,000 से अधिक सैटेलाइट

वाशिंगटन।

अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते उपग्रहों और अंतरिक्ष कबाड़ के कारण पृथ्वी की निचली कक्षा (लॉ अर्थ ऑर्बिट) में जाम लग सकता है। ऐसे में यह ऑर्बिट के इस्तेमाल को मुश्किल बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने अंतरिक्ष यातायात समन्वय पर कहा है कि अगर कंपनियों और देश मिलकर काम नहीं करेंगे और अंतरिक्ष के इस सबसे सुलभ क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जरूरी जानकारी साझा नहीं करेंगे तो यह समस्या और गंभीर हो जाएगी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए



इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा बनाने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका स्थित स्लिंगशॉट एपरोस्पेस ने बताया है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में 14,000 से ज्यादा

सैटेलाइट हैं, जिनमें 3,500 निष्क्रिय हैं। इनके साथ-साथ लॉन्च, टकराव और टूट-फूट से करीब 12 करोड़ मलबे के टुकड़े भी जमा हो गए हैं। इनमें से कुछ हजार ही इतने बड़े हैं कि उन पर नजर रखी जा सके। बाकी सभी बहुत छोटे टुकड़े हैं। मैनी ने कहा कि पृथ्वी की निचली कक्षा को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि वैश्विक संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक अन्वेषण के पीछे की तकनीक में महाने व्यवधान को रोका जा सके। अभी तक कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है जिसका सभी अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र लाभ उठा

'अब देरी नहीं करनी चाहिए'

संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय की निदेशक आरती होला मैनी का कहना है कि अंतरिक्ष यातायात समन्वय में देरी करने का समय नहीं है। अंतरिक्ष में इतनी सारी वस्तुएं भेजी जा रही हैं कि हमें अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इसका मतलब है कि टकराव से बचने के लिए ऑपरेटर्स के बीच सूचना साझा करना जरूरी है।

संकेत-उन्हें ऐसी प्रणाली का उपयोग करने के लिए राजी करने में भी कई बाधाएं हैं। कुछ देश डेटा साझा करने को तैयार हैं, जबकि अन्य सुरक्षा से समझौता करने से इतरते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा वह क्षेत्र है जो मानव निर्मित वस्तुओं से सबसे अधिक भरा हुआ है। यह लागत और निष्कृता के बीच संतुलन प्रदान करता है। यह तेजी से बढ़ते

वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इसे एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। स्लिंगशॉट के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले एक साल में प्रति उपग्रह नजदीकी दृष्टिकोण में 17 फीसदी की वृद्धि हुई है। अनुमान बताते हैं कि आने वाले वर्षों में हजारों और उपग्रह कक्षा में प्रवेश करेंगे। इसे जोखिम के और बढ़ने का अंदेशा है।